



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग 1—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 1999/कार्तिक 21, 1921

No. 255]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 1999/KARTIKA 21, 1921

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1999

विषय : यार्न, फैब्रिक्स और मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीति (2000—2004)—उन देशों के संबंध में जहां ऐसे निर्यात, वस्त्र एवं क्लोदिंग पर करार के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधों के अधीन हैं।

1. भूमिका

सं. 1/129/99-निर्यात-1.—संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा और यूरोपीय यूनियन को यार्न, फैब्रिक और मेड-अप मर्चें के निर्यात के संबंध में निर्यात और आयात नीति (1997—2002) के अंतर्गत प्रकाशित निर्यात और आयात के आई.टी.सी. (एच.एस.) वर्गीकरण के परिशिष्ट-1 की अनुसूची-2 की मद संख्या 8 में निहित उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2000 से 2004 तक के लिए हकदारियों के आबंटन की नीति (जिसे आगे आबंटन नीति कहा गया है) आगे दिए गए स्पष्ट विवरण अनुसार होगी।

2. संचालन :

§ 1§ जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए, कार्यकारी निदेशक, सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् §टेक्सप्रोसिल§ यूरोपीय यूनियन की श्रेणियों 3/3क और 23 को छोड़कर सभी यार्न, फैब्रिक और मेड-अप मर्चों की हकदारियों का आबंटन करेंगे। जबकि कार्यकारी निदेशक, सिंथेटिक व रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् §एस.आर.टी.ई.पी.सी.§ द्वारा आबंटन व प्रमाणन किया जाएगा तथा इसमें कनाडा की श्रेणी 31§क§ शामिल नहीं है जिसके लिए आबंटन कार्यकारी निदेशक, ऊन व ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् §डब्ल्यू. एण्ड डब्ल्यू.ई.पी.सी.§ द्वारा किया जाएगा। इन कार्यकारी निदेशकों को संबंधित देशों/श्रेणियों के लिए "कोटा संचालन प्राधिकारियों" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

§ 2§ उपर्युक्त प्रयोजन के लिए "कोट संचालन प्राधिकारियों" से तात्पर्य तथा इनमें शामिल ऐसे अन्य अधिकारियों से है जो कि आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करने, कार्य और उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए विधिवत प्राधिकृत हैं अथवा जिन्हें आवश्यक शक्तियों, कार्य और उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित किए गए हैं।

§ 3§ "कोट संचालन प्राधिकारियों" के होते हुए भी उनके द्वारा बनाया गया कोई भी प्रतिनिधिमंडल आर्बटन नीति के क्रियान्वयन के लिए वस्त्र मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी होंगे।

§ 4§ वस्त्र मंत्रालय इस अधिसूचना के उपबंधों में से किसी भी उपबंध की व्याख्या के संबंध में अंतिम प्रतिक्रिया होगा। वस्त्र मंत्रालय संचालन एजेंसियों, उनके कार्य तथा उत्तरदायित्वों के बारे में समय-समय पर ऐसे मार्गनिर्देशन भी जारी कर सकता है, जो उसे उपयुक्त प्रतीत होंगे तथा साथ ही, ऐसे अधिकारियों के आंशिक अथवा समग्र कार्य तथा उत्तरदायित्वों का भी पुनः आर्बटन कर सकता है, जो कि उसे उपयुक्त प्रतीत होंगे।

(5) निर्यात हकदारियों का आर्बटन केवल उन्हीं निर्यातकों को किया जाएगा जो कि समय-समय पर प्रचलित निर्यात-आयात नीति के अनुसार सक्षम पंजीकरण प्राधिकारियों के पास पंजीकृत हो।

3. आधार वर्ष :

इस अधिसूचना में किसी भी स्थान पर आने वाले "आधार वर्ष" वाक्यांश का अभिप्राय किसी भी आर्बटन वर्ष के लिए उस क्लेन्डर वर्ष से होगा जो उस आर्बटन वर्ष के पूर्व वर्ष से ठीक पहले आया हो। उदाहरणार्थ, आर्बटन वर्ष 2000 के लिए आधार वर्ष 1998 होगा।

4. आर्बटन की प्रणालियाँ :

§ 1§ प्रत्येक आर्बटन वर्ष में निर्यात के लिए मात्राओं का आर्बटन यार्न, फैब्रिक और मेड-अप्स § जिनमें हथकरघा मेड-अप भी शामिल हैं § के लिए प्रत्येक मद के सामने निर्विष्ट दरें पर निम्नलिखित प्रणालियों के अनुसार किया जाएगा।

आर्बटन की प्रणाली

वार्षिक स्तर का प्रतिशत

1. यार्न	
§ 1§ विगत निर्यात निष्पादन हकदारी §पी.पी.ई. § प्रणाली	55
§ 2§ विनिर्माता-निर्यातक हकदारी §एम.ई.ई. § प्रणाली	15
§ 3§ तैयार माल निर्यातकों की हकदारी §आर.जी.ई. § प्रणाली	30
2. फैब्रिक § श्रेणी 3, 3क/ई यू, 31क और 32क/कनाडा के अतिरिक्त § :	
§ 1§ विगत निर्यात निष्पादन हकदारी §पी.पी.ई. § प्रणाली	55
§ 2§ विनिर्माता-निर्यातक हकदारी §एम.ई.ई. § प्रणाली	15
§ 3§ विद्युतकरघा निर्यातकों की हकदारी §पी.पी.ई. § प्रणाली	15
§ 4§ तैयार माल निर्यातक हकदारी §आर.जी.ई. § प्रणाली	15
3. फैब्रिक § ई.यू./श्रेणी 3, 3क; कनाडा श्रेणी 31क और 32क के लिए § :	
§ 1§ विगत निर्यात निष्पादन हकदारी §पी.पी.ई. § प्रणाली	55
§ 2§ विनिर्माता निर्यातक हकदारी §एम.ई.ई. § प्रणाली	15

- § 3§ तैयार माल निर्यातकों की हकदारी §आर.जी.ई. § प्रणाली 30
4. मेड-अप §हथकरघा§यू.एस.ए. में मात्रा संबंधी प्रतिबंध के अंतर्गत §:
- § 1§ विगत निर्यात निष्पादन हकदारी §पी.पी.ई. § 55
- § 2§ तैयार माल निर्यातक हकदारी §आर.जी.ई. § प्रणाली 45
5. मेड अप §मिल निर्मित/विद्युतकरघा§:
- § 1§ विगत निर्यात निष्पादन हकदारी §पी.पी.ई. § प्रणाली 55
- § 2§ विनिर्माता निर्यातक हकदारी §यू.एस.ई. § प्रणाली 15
- § 3§ विद्युतकरघा निर्यातक हकदारी §पी.ई.ई. § प्रणाली 15
- § 4§ तैयार माल निर्यातक हकदारी §आर.जी.ई. § प्रणाली 15
- § 2§ उपर्युक्त के अतिरिक्त अभ्यर्पण, रियायतों अथवा अन्यथा के कारण समय-समय पर उपलब्ध होने वाली मात्राओं का आबंटन भी तैयार माल निर्यातक हकदारी §आर.जी.ई. § प्रणाली के अंतर्गत किया जाएगा ।
- § 3§ मौग पैटर्न अथवा प्रासंगिक कारकों में परिवर्तनों को देखते हुए यदि वांछनीय समझा गया तो उपरोक्त से भिन्न हकदारियाँ आबंटित करने का अधिकार भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के पास सुरक्षित होगा ।
5. विगत निर्यात निष्पादन हकदारी §पी.पी.ई. § प्रणाली :
आवेदन-पत्र तथा परीक्षण
- § 1§ इस प्रणाली में आबंटन के लिए उद्दिष्ट मात्राएँ 1 जनवरी को उपलब्ध कराई जाएंगी तथा इस प्रयोजन के लिए विगत वर्ष के दौरान कोटा संचालन प्राधिकारियों द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे ।
- § 2§ संबंधित "कोटा संचालन प्राधिकारी" विगत निर्यात निष्पादन हकदारी का परीक्षण करेंगे ।
- § 3§ उपलब्ध मात्रा का समानुपात आबंटन आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रत्येक देश श्रेणी में आधार वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के मूल्य के आधार पर किया जाएगा । तथापि, आबंटन को आधार वर्ष के दौरान उक्त देश §श्रेणी§ में भारत के वार्षिक औसत निर्यात की सीमा तक प्रतिबंधित कर दिया जाएगा ।
- आबंटन उपयोग तथा हस्तांतरणीयता
- § 4§ पी.पी.ई. दो भागों में आबंटित की जाएगी । प्रत्येक भाग में 50% आबंटन निश्चित होगा । पहला भाग आबंटन की तारीख से 31 मई तक वैध होगा तथा दूसरा भाग 30 सितम्बर तक वैध होगा ।
- § 5§ 31 मई तक वैध होने वाली पी.पी.ई. के मामले में हस्तांतरण की अनुमति अंतिम तारीख तक दी जाएगी लेकिन मूल कोटा धारक अथवा हस्तांतरी हकदारी के संबंध में लदान के प्रमाण-पत्र पर पृष्ठांकन 31 मई तक प्राप्त कर सकेगा । प्रमाणन कोटा वर्ष में 20 जून तक लदान के लिए वैध होगा । अनप्रयुक्त कोटे §गैर-प्रमाणीकृत अथवा लदान न किए गए कोटे§ समाप्त हो जायेंगे ।
- § 6§ 30 सितम्बर तक वैध पी.पी.ई. के मामले में हस्तांतरण की अनुमति 20 सितम्बर तक दी जाएगी और कोटाधारक अथवा हस्तांतरी नीचे दी गई दृष्टि पर बैंक गारंटी/पेशगी जमा धनराशि का भुगतान करने पर 31 दिसम्बर तक बढ़ी हुई अवधि प्राप्त कर सकता है जो कि इस शर्त

पर होगी कि यह बढ़ी हुई अवधि विशिष्ट क्रेता के लिए प्राप्त की जाती है। कोटा संचालन प्राधिकारियों द्वारा लागू अन्य शर्तों में परिवर्तन किए बिना क्रेता को एक बार बदलने की अनुमति दी जा सकती है।

उत्पाद समूह	राशि
यूरोपीय यूनियन/यू.एस.ए. के यार्न	5 ₹0 प्रति कि०ग्रा०
यूरोपीय यूनियन के फैब्रिक और मेड-अप मर्चे	10 ₹0 प्रति कि०ग्रा०
यू.एस.ए./कनाडा के फैब्रिक और मेड-अप मर्चे	2 ₹0 प्रति वर्ग मी० अथवा 2 ₹0 प्रति दर्जन अथवा 2 ₹0 प्रति कि०ग्रा०, जैसा भी मामला है।
अन्य कोई मर्च	पोस्टपर्यंत निःशुल्क मूल्य का 5%

§ 7§ अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र हकदारी की प्रारंभिक वैधता के समाप्त होने से पहले अथवा तीन कार्य दिवसों की छूट दी गई अवधि के भीतर सभी तरह से परिपूर्ण करके प्रस्तुत करने होंगे।

§ 8§ हस्तांतरित पी.पी.ई. को पी.पी.टी. के नाम से जाना जाएगा।

§ 9§ पी.पी.टी. के आधार पर लदानों का परिकल्पन हस्तांतरी द्वारा निर्यात के रूप में किया जाएगा।

§ 10§ पी.पी.टी. के हस्तांतरण की अनुमति नहीं है।

6. विनिर्माता निर्यातक हकदारी § पम-ई.ई. प्रणाली :

आवेदन पत्र तथा परिकल्पन

§ 1§ इस प्रणाली के अंतर्गत आबंटन ऐसे विनिर्माता निर्यातकों को किया जाएगा जिन्होंने आधार अवधि के दौरान अपने संयंत्र और मशीनों का पर्याप्त आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी का उन्नयन कर लेंगे। ऐसे संयंत्र और मशीनें इस समय लागू प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना के पात्रता मानदण्ड को पूरा करेगी।

§ 2§ इस प्रणाली के अंतर्गत आबंटन केवल आधुनिकीकृत और उन्नत उत्पादन एकक में विनिर्मित माल के निर्यात के लिए ही किया जाएगा।

§ 3§ आबंटित लदान के प्रमाणन के समय इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि निर्यात की जा रही वस्तुएँ उनके आधुनिकीकृत/उन्नत उत्पादन एककों में विनिर्मित की गई हैं।

§ 4§ वर्ष 2000 के लिए आधार अवधि 4 वर्षों अर्थात् 1.7.95 से 30.6.1999 तक की होगी। तथापि, आबंटन वर्ष 2001 से आधार अवधि तीन वर्ष की होगी। उदाहरणार्थ, वर्ष 2000 के लिए आधार अवधि 1.7.1997 से 30.6.2000 तक, वर्ष 2002 के लिए आधार अवधि 1.7.1998 से 30.6.2001 तक की होगी तथा आगे भी यही क्रम रहेगा। वर्ष 2000 के मामले में आवेदन पत्र पृथक रूप से जारी किए जाने वाले मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के अनुसार आबंटित किए जायेंगे।

- § 5§ एम.ई.ई. के लिए आवेदन पत्र कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल द्वारा पिछले वर्ष की 30 सितम्बर तक प्राप्त किये जायेंगे। इस प्रणाली के अंतर्गत आवेदन पत्र के साथ कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल के पक्ष में आहरित 500 रु0 का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र की अन्य शर्तें वस्त्र आयुक्त द्वारा कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल के परामर्श से तथा वस्त्र मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद निश्चित की जायेंगी।
- § 6§ एम.ई.ई. के अंतर्गत उपलब्ध मात्राओं का वितरण संबंधित "कोटा संचालन प्राधिकारी" द्वारा पात्र आवेदकों की उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक पात्र आवेदक उपर्युक्त आबंधन के लिए अधिकतम 5 श्रेणियों का विकल्प दे सकते हैं।

आबंधन, उपयोग और हस्तांतरणीयता

- § 7§ एम.ई.ई. दो भागों में आबंटित की जाएगी। प्रत्येक भाग में 50% आबंधन निश्चित होगा। प्रथम भाग आबंधन की तारीख से 31 मई तक तथा द्वितीय भाग 30 सितम्बर तक वैध होगा।
- § 8§ 31 मई तक वैध एम.ई.ई. के मामले में कोटाधारक हकदारी के संबंध में लदान के प्रमाणन पर पृष्ठांकन 31 मई तक प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रमाणन लदान के लिए कोटा वर्ष में 20 जून तक वैध होगा। अनप्रयुक्त कोटे § गैर-प्रमाणित अथवा लदान न किए गए कोटे समाप्त हो जायेंगे।
- (9) 30 सितम्बर तक वैध एम.ई.ई. के मामले में कोटाधारक 5 (6) में उल्लिखित अन्य शर्तों में आवश्यक परिवर्तन के अध्यक्षीन तथा दरों पर बैंक गारंटी/पेशगी जमा धन राशि का भुगतान करने पर 31 दिसम्बर तक बढ़ी हुई समयावधि प्राप्त कर सकते हैं।
- § 10§ बढ़ी हुई अवधि के लिए सभी तरसे से परिपूर्ण ऐसे आवेदन पत्र तीन कार्यदिवसों की छूट अवधि के भीतर अथवा हकदारी की प्रारंभिक वैधता की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत करने होंगे।
- § 11§ एम.ई.ई. हस्तांतरणीय नहीं होगी।

7. विद्युतकरषा नियंत्रित हकदारी § पी.ई.ई. § प्रणाली :

वस्त्र आयुक्त वस्त्र मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद पी.ई.ई. प्रणाली के अंतर्गत आबंधन के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा पात्रता के मानदण्डों को पृथक रूप से अधिसूचित करेंगे।

8. तैयार माल हकदारी § आर.जी.ई. § प्रणाली :

जारी करने की अनुसूची

- § 1§ तैयार माल हकदारी प्रणाली के अंतर्गत हकदारी वर्ष में चार बार खुलेगी। ऐसी हकदारी का 40% भाग 10 जनवरी, 30% 10 अप्रैल, 20% 10 जुलाई तथा 10% 10 अक्टूबर को जारी किया जाएगा।
- § 2§ इस प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध मात्राओं के अतिरिक्त अभ्यर्पण, रियायतों अथवा अन्यथा उपलब्ध होने वाली मात्रा, वस्त्र मंत्रालय के अनुमोदन से संबंधित कोटा प्रचालन प्राधिकारी द्वारा व्यापार क्षेत्र को पर्याप्त सूचना देने के बाद किसी भी समय जारी किया जा सकता है।

आवेदन पत्र

- § 3§ मात्राओं का आबंटन आवेदन पत्रों के आधार पर तथा मात्राओं के उपलब्ध होने के दिन किया जाएगा, जिसकी पात्रता उस दिन प्राप्त आवेदन पत्रों में से इकाई मूल्य वसूली के आधार पर निर्धारित की जाएगी ।

आबंटन की वैधता

- § 4§ आबंटन की तारीख से 50 दिनों के लिए आबंटन वैध होगा । इसकी अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी ।

आबंटन की प्रणाली

- § 5§ आर.जी.ई. प्रणाली के अंतर्गत आबंटन अन्तरप्रस्त मात्रा के पोतपर्यंत निःशुल्क मूल्य के 5% की दर से ई.एम.डी./बैंक गारंटी के अध्यधीन होंगे ।
- § 6§ वस्त्र आयुक्त किसी आवेदक द्वारा संबंधित कोटा संचालन प्राधिकारी के परामर्श से प्रतिदिन इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक देश-श्रेणी के लिए आवेदक द्वारा आवेदित अधिकतम मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं ।

हस्तांतरणीयता

- § 7§ आर.जी.ई. आबंटन हस्तांतरणीय नहीं होंगे ।

हथकरघा के लिए आरक्षण

- § 8§ यू.एस. श्रेणी 363 के अंतर्गत टेबेटावल की एक लाख अदद मात्रा हथकरघा के लिए आरक्षित होगी । मंत्रालय किसी भी अन्य लागू देश/श्रेणी के अंतर्गत हथकरघा के लिए मात्राओं का आरक्षण भी कर सकता है ।

9. प्रमाणन की वैधता :

- § 1§ आर.जी.ई. प्रणाली के अंतर्गत प्रमाणन की वैधता यदि अन्यथा विनिश्चित नहीं किया गया है तो आबंटन की तारीख से 50 दिनों की अवधि के लिए होगी ।
- § 2§ पी.पी.ई./एम.ई.ई./पी.पी.टी. की वैधता लदान जिल के पृष्ठांकन की तारीख से 50 दिनों के लिए अथवा हकदारी प्रमाण पत्र के समाप्त होने, इसमें से जो भी पहले हो तक होगी ।
- § 3§ उपर्युक्त पैरा 8§4§ में प्रमाण के बावजूद वस्त्र आयुक्त अलग-अलग मामलों में वैधता अवधि को तीन कार्यदिवसों तक बढ़ा सकता है, बशर्ते कि वह इस बात से संतुष्ट हो कि संबंधित निर्यातक उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात नहीं कर सकता है ।

10. कम कारोबार की मदें :

- § 1§ किसी मद को कम कारोबार वाली मद के रूप में तभी अधिसूचित किया जाएगा जबकि आधार वर्ष के दौरान उसका उपयोग, उक्त वर्ष के वार्षिक स्तर के 75% से कम रहा हो । कोटा संचालन प्राधिकारी कम कारोबार वाली मदों के बारे में विगत वर्ष के 1 दिसम्बर तक अवश्य अधिसूचित कर देंगे ।
- § 2§ कम कारोबार वाली मदों के लिए इस अधिसूचना के किसी भी उपबंध में निहित व्यवस्था के बावजूद जहाँ कहीं भी ई.एम.डी./बी.जी. लागू होती है, वहाँ यह तैयार निर्यातक

- हकदारों प्रणाली के अंतर्गत माल लदान के लिए एफ.ओ.बी. मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से प्रभारित होगी ।
- § 3§ उपर्युक्त 8 में आर.जी.ई. प्रणाली के लिए निर्धारित मात्रा संबंधी उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी ।
- § 4§ तथापि, यह छूट किसी पूर्व सूचना के वापिस ली जा सकती है ।
11. पेशगी जमा राशि/बैंक गारंटी/उत्तर दिनांकित बैंक प्रस्तुत तथा जन्त करने के बारे में प्रावधान :
- § 1§ पेशगी जमा राशि § ई.एम.डी. § सामान्यतः डिमांड ड्राफ्ट, एफ.डी.आर. के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी, जो कि एकपक्षीय रूप से कोटा संचालन प्राधिकारी अथवा बैंक गारंटी द्वारा नकद प्राप्त किया जा सकता है । तथापि, आर.जी.ई. के अतिरिक्त अन्य प्रणालियों में उत्तर दिनांकित बैंक भी पेशगी जमा राशि के रूप में निम्नलिखित निर्धारित शर्तों पर स्वीकार्य होगा :
- § क§ हकदारियों को बढ़ाने के लिए आर.जी.ई. के अतिरिक्त अन्य प्रणालियों में उत्तर दिनांकित बैंक ई.एम.डी. के रूप में इस शर्त पर स्वीकार्य होंगे कि यदि बैंक किसी भी कारण से जमा करने के लिए अस्वीकृत कर दिया जाता है तो ऐसे बैंकों के आधार पर बढ़ाई गई मात्राएँ संबंधित निर्यातक की किसी भी प्रकार की भावी हकदारियों के नामे डाल दी जाएगी और उसे तब तक आगे हकदारी आर्बीट्रेट नहीं की जाएगी जब तक कि जन्त की गई राशि को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लौटया नहीं जाता । यह ऐसी किसी अन्य कानूनी अथवा अन्य उपचार के अतिरिक्त होगा जो कि कोटा संचालन प्राधिकारी करने का निर्णय ले सकता है ।
- § ख§ उत्तर दिनांकित बैंकों पर आर्बिट्रेशन के वर्ष के बाद के वर्ष की 1 जून की तारीख अंकित होनी चाहिए और ये उक्त तारीख से छः महीनों की अवधि के दौरान प्रस्तुत करने के लिए वैध होने चाहिए ।
- § ग§ उत्तर दिनांकित बैंकों को जारी/जन्त करने से संबंधित शर्तें वही होंगी जो कि ई.एम.डी./बैंक गारंटी के अन्य रूपों पर लागू हैं ।
- § 2§ अपनी हकदारी के 90% अथवा उससे अधिक का निर्यात करने वाले निर्यातक की ई.एम.डी./बैंक गारंटी/उत्तर दिनांकित बैंक की राशि पूरी रिलीज कर दी जाएगी । तथापि, कम कारोबार वाली मदों के बारे में यह प्रतिशत 75% अथवा अधिक होगा ।
- § 3§ "कोटा संचालन प्राधिकारी" अधिक कारोबार वाली मदों के मामले में 75% अथवा उससे अधिक का लेकिन 90% से कम उपयोग होने तथा कम कारोबार वाली मदों के मामले में 50% अथवा उससे अधिक लेकिन 75% से कम उपयोग होने की स्थिति में ई.एम.डी./बी.जी. को उपयोग में कमी के समानुपात में जन्त कर लेगा ।
- § 4§ यदि उपयोग उपर्युक्त से कम रहता है अर्थात् अधिक कारोबार वाली मदों के मामले में 75% तथा कम कारोबार वाली मदों के मामले में 50% से कम रहता है तो ई.एम.डी./बी.जी./उत्तर दिनांकित बैंक की पूरी राशि जन्त कर ली जाएगी ।
- § 5§ उपर्युक्त प्रयोजन के लिए उपयोग का परिकल्पित पृथक हकदारियों के आधार पर अथवा प्रत्येक प्रणाली के आधार पर पृथक रूप से अथवा सभी प्रणालियों § आर.जी.ई. प्रणाली को छोड़कर § एक साथ मिलाकर निर्यातक के निर्यात निष्पादन के लिए उसके अनुरोध पर किया जाएगा ।

- § 6§ जन्त करने से पूर्व एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा ।
- § 7§ कोटा संचालन प्राधिकारी बी.जी./ई.एम.डी./उत्तर दिनांकित बैंक आदि के जन्तीकरण के आदेश को पावती सहित पंजीकृत डाक अथवा प्राथमिक रूप से स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित करेगा । आदेश को भेजने का साक्ष्य उपर्युक्त विनिश्चित माध्यमों से तथा साथ ही उसकी पावती अथवा आदेश के प्रेषण के अन्य साक्ष्य संबंधित फाइल में रखने चाहिए ।
- § 8§ सभी जन्त किए गए ई.एम.डी./बी.जी./उत्तर दिनांकित बैंक सरकार के लोक जमा खाते में उस तरीके से जमा किए जायेंगे जैसा कि सरकार समय-समय पर निर्देश करेगी ।
- § 9§ जन्त की गई राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कोटा संचालन प्राधिकारी निर्यातक को विनिश्चित अवधि के लिए हकदारियाँ प्राप्त करने तथा निर्यात हकदारी वितरण प्रणाली में भाग लेने के लिए अस्थायी रूप से निकाल सकता है ।
12. रेके गए प्रेषणों को जारी करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त :
- § क§ जब आयातक देश द्वारा किसी गैर प्रतिबंधित श्रेणी में किए गए लदान को पुनः वर्गीकृत करके प्रतिबंधित श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जाता है अथवा जब आयातक देश द्वारा प्रतिबंधित श्रेणी में किए गए लदान को पुनः वर्गीकृत करके अन्य प्रतिबंधित श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में पुनः वर्गीकृत श्रेणी में निहित मात्रा को निर्यातक द्वारा अभ्यर्पित करने के बाद ही पुनः वर्गीकृत श्रेणी में निर्यात प्रमाण पत्र/बीजा जारी किए जायेंगे । इस प्रयोजन के लिए निर्यातक आर.जी.ई. से अन्यत्र प्रणालियों में अपनी हकदारियों में से अथवा अन्तरण द्वारा मात्रा प्राप्त करके मात्रा को अभ्यर्पित कर सकता है । यदि मामले को 20 सितम्बर के बाद निपटया जाना है तो उस स्थिति में हस्तांतरण की अनुमति न होने तथा निर्यातक के पास अपनी हकदारियों में से मात्रा अभ्यर्पित न कर पाने की स्थिति में ऐसे निर्यातक से इस आशय की वचनबद्धता प्राप्त कर ली जाएगी कि वह परवर्ती वर्ष की हकदारी § निजी अथवा हस्तांतरित § में से 31 जनवरी तक अपेक्षित मात्रा अभ्यर्पित कर देगा । इस प्रकार की वचनबद्धता के साथ उपर्युक्त पैरा 5§6§ में उल्लिखित दरों पर परिकल्पित की गई मात्रा के 50% मूल्य के बराबर की बैंक गारंटी/ई.एम.डी. प्रस्तुत करनी होगी । यदि वचनबद्धता के अनुसार मात्रा अभ्यर्पित नहीं की जाती है तो बैंक गारंटी/ई.एम.डी. जन्त की जा सकती है । ऐसे मामलों में परवर्ती वर्ष के लिए निर्यातक को किसी भी देश-श्रेणी में अपेक्षित मात्रा को अभ्यर्पित करने के बाद ही पी.पी.ई. का आबंटन किया जा सकता है ।
- § ख§ यदि आर.जी.ई. प्रणाली में कोटा संचालन प्राधिकारी द्वारा रिलीज की गई मात्राओं में से पुनः वर्गीकृत श्रेणियों में अनावर्तित अधिशेष मात्रा उपलब्ध होती है तो ऐसी अधिशेष मात्रा को नामें डालने के बाद ही रेके गए प्रेषण के लिए निर्यात प्रमाण पत्र/बीजा जारी किया जाएगा और निर्यातक को कोई भी मात्रा अभ्यर्पित नहीं करनी पड़ेगी ।
- § ग§ उपर्युक्त § क § और § ख § में उल्लिखित शर्तें ऐसे मामलों पर भी लागू होंगी जहाँ आर.जी.आई. प्रणाली के अंतर्गत अथवा 30 सितम्बर के बाद प्राप्त की गई बट्टे हुई अवधि के बाद पी.पी.ई./एम.ई.ई. के अंतर्गत किए गए लदान के लिए क्रेता को बदलना अपेक्षित है तथा ये शर्तें उन मामलों पर भी लागू होंगी जिनमें आयातक देश को बदलना अपेक्षित है ।

§ ५॥ जहाँ गैर-प्रतिबंधित श्रेणी में किए गए निर्यात को उपर्युक्त किसी अन्य गैर-प्रतिबंधित श्रेणी में पुनः वर्गीकृत किया जाता है तो देश से लदान करने के लिए प्रयुक्त की गई हकदारी निम्नलिखित शर्तों पर निर्यातक को लौटाई जा सकती है :

§ 1॥ निर्यातक द्वारा संबंधित कोटा संचालन प्राधिकारी को मूल निर्यात प्रमाण पत्र/वीजा वापिस लौटाना ।

§ 2॥ निर्यात के समय नामे डाला गया हकदारी प्रमाण पत्र, हकदारी को पुनः वापिस करने का अनुरोध करने पर संबंधित मात्रा के लिए वैध रहता है ।

§ ३॥ प्रतिबंधों से छूट प्राप्त हथकरघा परिधानों अथवा "भारतीय मर्दों" के रूप में निर्यात की गई ऐसी मर्दों के मामले में जिन्हें आयातक देश द्वारा प्रतिबंधित मर्दों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है, वस्त्र मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही कोटा संचालन प्राधिकारी द्वारा वीजा/निर्यात प्रमाण पत्र जारी किए जायेंगे ।

13. सीमा शुल्क विभाग द्वारा निम्नलिखित :

§ 1॥ प्रतिबंध अधीन उत्पाद : पोतलदान कन्वरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पोतलदान की अनुमति, निर्यात हकदारी के प्रमाणन के मूल पत्रों की तथा टेक्सप्रोसिल अथवा इस प्रयोजनार्थ मनोनीत किसी अन्य उपयुक्त अभिकरण द्वारा अलग-अलग माल के लिए जारी किए गए शिपिंग बिलों की जाँच करने के बाद दी जाएगी ।

§ 2॥ हथकरघा उत्पाद : जहाँ तक प्रतिबंधित मर्दों के समानरूप समस्त हथकरघा फैब्रिक/मेड अप मर्दों के निर्यात का संबंध है, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निर्यात की अनुमति वस्त्र समिति द्वारा संयोजन प्रपत्र के भाग-2 में निरीक्षण संबंधी पृष्ठांकन के आधार पर दी जाएगी ।

§ 3॥ "भारतीय मर्द" के अंतर्गत आने वाली मेड-अप मर्दें : भारतीय मर्द के संबंध में जो कि भारत की परम्परागत लोक रीति के हस्तशिल्प की वस्त्र उत्पाद मर्दें हैं, उनका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, कनाडा तथा नार्वे को निर्यात करने के उद्देश्य से पोतलदान की अनुमति सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा विकास आयुक्त § हस्तशिल्प § कार्यालय के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए उपयुक्त प्रमाण पत्रों के आधार पर दी जाएगी ।

14. निर्यात प्रमाण पत्र, मूल स्थान का प्रमाण पत्र तथा वीजा :

संबंध विपक्षीय प्रबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमाणन संबंधित कोटा संचालन प्राधिकारी अथवा उसकी ओर से विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य निकाय द्वारा जारी किया जाएगा :-

§ 1॥ संयुक्त राज्य अमेरिका : टेक्सप्रोसिल द्वारा सभी यार्न, फैब्रिक § हथकरघा को छोड़कर § और मेड-अप § हथकरघा सहित § के वाणिज्यिक मूल्य के प्रेषण के लिए वीजा जारी किये जायेंगे ।

§ 2॥ यूरोपीय यूनियन : § क § कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल द्वारा श्रेणी 3/3 § क § और श्रेणी 23 को छोड़कर यार्न, फैब्रिक और मेड-अप की सभी प्रतिबंधित मर्दों के लिए निर्यात प्रमाण पत्र और मूल स्थान के प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे; § ख § कार्यकारी निदेशक, एस.आर. टी.ई.पी.सी. द्वारा यूरोपीय यूनियन की श्रेणी 3/3 § क § और 23 के लिए निर्यात प्रमाण पत्र और मूल स्थान का प्रमाण पत्र जारी किए जायेंगे; § ग § संबंधित कोटा संचालन प्राधिकारी द्वारा सभी गैर-प्रतिबंधित मर्दों के लिए मूल स्थान के प्रमाण पत्र जारी किए जायेंगे ।

§ 3॥ कनाडा : कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल द्वारा 500 कनाडियन डालर से कम मूल्य के प्रेषणों को छोड़कर प्रतिबंधन के अधीन फैब्रिक § श्रेणी 31 § क § को छोड़कर § और मेड-अप मर्दों के लिए प्रमाण पत्र जारी किए जायेंगे । कार्यकारी निदेशक, डब्ल्यू.डब्ल्यू.ई.पी.सी. द्वारा श्रेणी 31 § क § के लिए निर्धारित प्रमाण पत्र जारी किए जायेंगे ।

15. हथकरघा पर छूट प्रमाण पत्र :

कनाडा को प्रतिबंधित मर्दों के समानुरूप समस्त हथकरघा फैब्रिक, मेड अप मर्दों, यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका को समस्त हथकरघा फैब्रिक तथा मेड अप मर्दों के मामले में ऐसे उत्पादों के लिए वस्त्र समिति विपक्षीय करारों में यथा निर्धारित प्रमाण पत्र जारी करेगी ।

16. ई-एम-डी./बी जी/ उत्तर दिनांकित चैक को जप्त करने पर अपील

- § 1§ कोटा संचालन प्राधिकारी द्वारा ई एम डी/बी जी को जप्त करने के आदेश से कथित निर्यातक, प्रथम अपील प्राधिकारी अर्थात् वस्त्र आयुक्त को, कोटा संचालन प्राधिकारी के आदेश के प्रेषण के 45 दिनों के भीतर अपील वायर कर सकता है । यह अपील तीन प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी जिसके साथ वस्त्र आयुक्त के पक्ष में तथा मुम्बई में देय 500 ₹0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा ।
- § 2§ अपील कर्ता यदि चाहे तो कोटा संचालन प्राधिकारी के आदेश के स्थगन के लिए एक प्रथम आवेदन पत्र भी प्रस्तुत कर सकता है ।
- § 3§ वस्त्र आयुक्त स्थगन के मुद्दे पर यथाशीघ्र निर्णय देंगे ।
- § 4§ अपील पर भी निर्णय अधिमानता यथा शीघ्र अर्थात् दो महीनों के भीतर ले लिया जाएगा । यदि अपील कर्ता द्वारा अनुरोध किया जाता है तो उसे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपयुक्त अवसर दिया जाएगा । अन्तिम आदेश पंजीकृत डाक द्वारा §पावती के कार्ड सहित§ अथवा अधिमानतः स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया जाएगा तथा उक्त माध्यम से उसके प्रेषण के प्रमाण के साथ उसकी पारवती/रसीद सहित अथवा अन्यथा संबंधित फाइल में रखने होंगे ।
- § 5§ वैध तारीख के बाद वायर की गई अपील के मामले में वस्त्र आयुक्त प्रथमतः यह निर्णय लेंगे कि क्या ऐसे चिर्लब को माफ कर दिया जाए अथवा नहीं । वस्त्र आयुक्त ऐसे मामलों में मौखिक आदेश देंगे ।
- § 6§ उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए वस्त्र आयुक्त से तात्पर्य तथा ऐसे शामिल किए गए अन्य अधिकारी §जो कि निदेश के पद के नीचे नहीं होगा§ से है जिसे वस्त्र आयुक्त स्पष्ट रूप से अथवा अन्यथा आवश्यक उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित करते हैं ।
- § 7§ यदि कोई निर्यातक स्थगन के आवेदन पत्र या अपील के मामले में वस्त्र आयुक्त के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वह प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश के प्रेषण के 45 दिनों के भीतर ऐसे निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील प्राधिकारी को उस पर निर्णय लेने के लिए अपील वायर कर सकता है ।
- § 8§ इन प्रयोजनों के लिए द्वितीय अपील समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :-
- | | |
|---|------------|
| §क§ संयुक्त सचिव/निर्यात§, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार | अध्यक्ष |
| §ख§ विधि व न्याय मंत्रालय का एक अधिकारी, भारत सरकार | सदस्य |
| §जो कि भारत सरकार में उप सचिव के पद से नीचे नहीं होगा§ | |
| §ग§ महानिदेशक, विदेश व्यापार, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार | |
| का एक अधिकारी§जो कि भारत सरकार में उप सचिव के पद से नीचे नहीं होगा§ | सदस्य |
| §घ§ उप सचिव/निदेशक/निर्यात§, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार | सदस्य सचिव |
| इस समिति के कोरम में इसके अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे । | |

- § 9§ द्वितीय अपील प्राधिकारी के समक्ष दायर की जाने वाली कोई भी अपील, उसके सदस्य सचिव को संबंधित होगी जिसकी पाँच प्रतियों के साथ वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में तथा विल्ली में देय 500 रु० का डिमाण्ड डाफ्ट संलग्न करना होगा ।
- § 10§ यदि अपील की विषय वस्तु भी स्थगन से संबंधित होती है तथा वह तात्कालिक प्रवृत्ति की है तो समिति के अध्यक्ष लिखित रूप से कारणों को दर्ज करके, स्थगन की स्वीकृति दे सकते हैं।
- § 11§ द्वितीय अपील प्राधिकारी भी मामले पर यथा शीघ्र अधिमानतः तीन महीनों के भीतर निर्णय ले लेंगे ।

17. नियतियों द्वारा कोटा संबंधी कवाचार से निपटने की प्रक्रिया

- § 1§ प्रवर्तन समितियाँ नामक समितियाँ स्थापित की जायेंगी जिनका गठन निम्नानुसार होगा:-

- | | |
|---|------------|
| § 1§ वस्त्र आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार | अध्यक्ष |
| § 2§ कोटा संचालन प्राधिकारी | सदस्य |
| § 3§ विधि व न्याय मंत्रालय, भारत सरकार § जो कि भारत सरकार में उप सचिव के पद से नीचे नहीं होगा § | सदस्य |
| § 4§ संबंधित एजेंसी के अध्यक्ष § टेक्सप्रोसिल, एस.आर.टी.ई.पी.सी. तथा डब्ल्यू डब्ल्यू ई पी सी जैसी भी स्थिति होगी § | सदस्य |
| § 5§ संबंधित एजेंसी का एक अधिकारी § जिसे कोटा संचालन प्राधिकारी द्वारा प्रवर्तन समिति के अध्यक्ष के परामर्श से नामित किया जाएगा § | सदस्य सचिव |
- § 2§ समिति का कोरम अध्यक्ष और दो सदस्यों से होगा ।
- § 3§ प्रवर्तन समिति ऐसे मामलों पर विचार करेगी जिसमें कि कोटा प्राप्त करने, इसकी अवधि बढ़ाने, कोटा का उपयोग करने या कोटा के उपयोग को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक का ही प्रयोग किया गया हो :-
- § क§ कोई भी कपटपूर्ण कार्य
 - § ख§ तथ्यों का अयथार्थ विवरण
 - § ग§ दस्तावेजों का अन्यायपूर्ण या जालसाजी
 - § घ§ हकदारियों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए ऐसे उत्तर विनियमित चेक देना जिनका बैंक में प्रस्तुत करने पर भुगतान न हो ।
- § 4§ प्रवर्तन समिति ऐसे मामलों पर भी विचार करेगी जिनमें यह पाया गया हो कि किसी नियमित ने किसी ऐसी वस्तु का निर्यात किया हो या निर्यात करने के लिए औपचारिकताएँ पूरी की हो, जिसमें कि किसी ऐसे रंग, रसायन, रंगद्रव्य या अन्य वस्तु का प्रयोग किया हो जिस पर सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा विशेष रूप से प्रतिबन्ध लगाया गया हो ।
- § 5§ उन मामलों में जहाँ समिति निर्यातक के स्पष्टीकरण की जाँच करने तथा उसे व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देने के पश्चात् निर्यातक घोखाधड़ी या अन्य अनियमितताओं जो कि ऊपर लिखित किसी भी प्रावधान के उल्लंघन करने के लिए दोषी पाती हैं, तो निर्यातक को विशिष्ट अवधि के लिए हकदारियाँ प्राप्त करने तथा निर्यात हकदारी वितरण प्रणाली में भाग लेने से विवर्जित किया जाये ।

§ 6§ गम्भीर मामलों में कोटा संचालन प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई से पहले, प्रक्रिया के पूरा हुये बिना तथा समिति द्वारा निर्णय के अन्तिम रूप देने से पूर्व निर्यातिक को अस्थाई तौर पर विचारित किया जा सकता है ।

§ 7§ प्रवर्तन समिति के निर्णयों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई एक प्रवर्तन अपील समिति करेगी जिसका गठन निम्नोक्त अनुसार होगा :-

§ 1§ संयुक्त सचिव/निर्याति, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार अध्यक्ष

§ 2§ विधि एवं न्याय मंत्रालय का एक अधिकारी जो कि भारत सरकार में उप सचिव के पद से नीचे नहीं होगा सदस्य

§ 3§ महानिदेशक, विदेश व्यापार कार्यालय, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार का एक अधिकारी जो कि भारत सरकार में उपसचिव के पद से नीचे नहीं होगा सदस्य

§ 4§ उप सचिव/निदेशक/निर्याति, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार सदस्य सचिव

§ 8§ प्रवर्तन अपील समिति का कोरम अध्यक्ष और 2 सदस्यों से होगा । तथापि, प्रवर्तन अपील समिति को, लिखित रूप के कारण दर्ज करने के बाद प्रवर्तन समिति द्वारा पारित आवेदों पर स्थगन की स्वीकृति देने की शक्ति होगी ।

§ 9§ प्रवर्तन अपील समिति के समक्ष कोई भी अपील पाँच प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी जिसके साथ वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में 500 रु० का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा ।

§ 10§ प्रवर्तन अपील समिति निर्यातिक से अपील प्राप्त होने पर अथवा टेक्सप्रोसिल सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्याति संवर्धन परिषद से स्वयं ब्योरे मंगा कर प्रवर्तन समिति के आवेदों की समीक्षा संशोधन, आशोधन कर सकती है अथवा उनको रद्द कर सकती है ।

18 • वस्त्र आयुक्त की पर्यवेक्षकीय भूमिका

वस्त्र आयुक्त, इस नीति के क्रियान्वयन से संबंधित मामलों का सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे । वस्त्र आयुक्त को यदि किसी प्रकार के विचलन के बारे में पता चलता है तो वे उस पर निर्देश प्रान्त करने के लिए उसे तत्काल वस्त्र मंत्रालय को सूचित करेंगे ।

19 • समन्वय समिति

समन्वय समिति में वस्त्र आयुक्त, निर्याति संवर्धन परिषदों ए ई पी सी, टेक्सप्रोसिल, एस आर टी ई पी सी और डब्ल्यू डब्ल्यू ई पी सी के प्रतिनिधियों सहित कोटा संचालन प्राधिकारी, कार्यकारी निदेशक, एच ई पी सी, विकास आयुक्त इस्तराशात्प तथा उप सचिव/निदेशक/निर्याति शामिल होंगे । समिति नीति के प्रचालन की पुनरीक्षा करने के लिए तीन महीनों में एक बार संयुक्त सचिव/निर्याति की अध्यक्षता में बैठक करेगी । समिति नीति में वांछित किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए एक रिपोर्ट मंत्रालय को भेजेगी ।

20 • सरकार का संशोधन करने का अधिकार

सरकार के पास, कोई पूर्व सूचना दिए बिना, लोक हित में, उपयुक्त उपबंधों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th November, 1999

Subject :—YARN, FABRICS & MADE-UPS EXPORT ENTITLEMENT (QUOTA) POLICY FOR (2000—2004)—
in respect of countries where such exports are covered by restraints under the provisions of the Agree-
ment on Textiles and Clothing.

1. INTRODUCTION

No. 1/129/99-Exports-I—Pursuant to the provisions contained in Item No. 8 of Appendix I, schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export and Import published under the Export and Import Policy (1997—2002) in respect of exports of Yarn, Fabric and Made-up items to the USA, Canada and the European Union, the Policy for allotment of entitlements, (hereinafter referred to as the Allotment Policy) for the years 2000 to 2004 shall be as hereinafter detailed.

2. ADMINISTRATION

- i) Unless otherwise directed, the Executive Director, the Cotton Textiles Export Promotion Council (TEXPROCIL) shall allocate entitlements of all Yarn, Fabric and Made-up items, except for EU categories 3/3a and 23, allotments and certification of which will be made by the Executive Director, Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council (SRTEPC) and except for CANADA Category 31(a) for which allotment will be made by Executive Director, Wool & Woollen Export Promotion Council (W&WEPC). These Executive Directors will be referred to as 'Quota Administering Authorities' for the respective country/categories.
- ii) For the purpose of the above, the 'Quota Administering Authorities' shall mean and include such other officials who are duly authorised to exercise the necessary powers, functions and responsibilities or who are delegated with necessary powers, functions and responsibilities.
- iii) The 'Quota Administering Authorities', notwithstanding any delegation effected by them, shall be accountable to the Ministry of Textiles for implementation of the Allotment Policy.
- iv) The Ministry of Textiles shall be the final authority regarding the interpretation of any of the provisions of this notification. The Ministry of Textiles may also issue such guidelines as it deems fit from time to time, regarding agencies of administration, their functions and responsibilities and may reallocate part or whole of the functions and responsibilities to such authorities as it deems fit.

- v) Export entitlements will be allotted only to exporters registered with the competent Registering Authorities as per the Export Import Policy prevailing from time to time.

3. BASE YEAR

The phrase “Base Year” for an allotment year, wherever appearing in the Notification shall mean the calendar year preceding the year immediately before that allotment year. For example, for the allotment year 2000, the base year shall be 1998.

4. SYSTEMS OF ALLOTMENT

- (i) Quantities for export in each allotment year shall be allocated according to the following systems at rates indicated against each of them for Yarn, Fabrics & Made-ups (including Handloom Made-ups).

<i>System of allotment</i>	<i>Percentage of annual level</i>
I. YARN :	
(i) Past Performance Entitlement (PPE) system	55%
(ii) Manufacturer Exporters Entitlement (MEE) system	15%
(iii) Ready Goods Entitlement (RGE) system	30%
II. FABRICS (other than for categories 3,3a/EU, 31a and 32a/Canada):	
(i) Past Performance Entitlement (PPE) system	55%
(ii) Manufacturer Exporters Entitlement (MEE) system	15%
(iii) Powerloom Exporters' Entitlement (PEE) system	15%
(iv) Ready Goods Entitlement (RGE) system	15%
III. FABRICS (for EU/category 3, 3a; Canada category 31a and 32/a):	
(i) Past Performance Entitlement (PPE) system	55%
(ii) Manufacturer Exporters Entitlement (MEE) system	15%
(iii) Ready Goods Entitlement (RGE) system	30%
IV. MADE-UPS (Handlooms) (under quantitative restraint in USA):	
(i) Past Performance Entitlement (PPE) system	55%
(ii) Ready Goods Entitlement (RGE) system	45%
V. MADE-UPS (Mill-made/powerlooms):	
(i) Past Performance Entitlement (PPE) system	55%
(ii) Manufacturer Exporters Entitlement (MEE) system	15%
(iii) Powerloom Exporters' Entitlement (PEE) system	15%
(iv) Ready Goods Entitlement (RGE) system	15%

- (ii) Apart from the above, quantities that become available from time to time on account of surrenders, flexibilities or otherwise shall also be allocated under the RGE System.

- (iii) The Ministry of Textiles reserves the right to allocate entitlements in variation with the above, in case it is considered so desirable in view of changes in demand patterns or other relevant factors.

5. PAST PERFORMANCE ENTITLEMENT (PPE) SYSTEM

Applications and Computation

- (i) The quantities earmarked for allotment in this system shall be made available on 1st January and for this purpose, applications shall be invited by the Quota Administering Authorities during the previous year.
- (ii) The 'Quota Administering Authority' concerned will compute PPE.
- (iii) Available levels will be allotted pro-rata on the value of exports during the base year by the applicants in each country-category. Allotments, however, will be restricted to the average annual export performance of India in the country-category during the base year.

Allotment, Utilisation and Transferability

- (iv) PPE will be allotted in two parts, each consisting of 50% of the allotment. The first part will be valid from the date of allotment till 31st May and the second part will be valid till 30th September.
- (v) In case of PPE valid till 31st May, the transfers shall be allowed till the last date but the original quota holder or the transferee will get the endorsement on the certification of shipment in respect of the entitlement by 31st May. The certification will be valid for shipment upto 20th June of the quota year. Unutilised quotas (non-certified or non-shipped) shall lapse.
- (vi) In case of PPE valid till 30th September, the transfers are allowed till 20th September and the quota holders or transferee can get the extension till 31st December on payment of BG/EMD at the rates given below, subject to the condition that the extension sought is for a specific buyer. One time change of buyer can be allowed by the Quota Administering Authority without changing other conditions applicable.

Product group	Amount
Yarn to the EU/USA	Rs.5 per kg.
Fabric and made-up items to the EU	Rs.10 per kg.
Fabric and made-up items to the USA/Canada	Rs.2 per Sq. Mtr. or Rs.2 per dozen, or Rs. 2 per kg. as the case may be.
Any other item	5% of FOB value

- (vii) The applications for such extension shall be submitted, complete in all respects, before the expiry of the initial validity of the entitlement or within a grace period of three working days.
- (viii) The transferred PPE will be known as PPT.
- (ix) Shipments against PPT shall be counted as exports by the transferee.
- (x) Transfer of PPT is NOT allowed.

6. MANUFACTURER EXPORTERS' ENTITLEMENT (MEE) SYSTEM

Applications and Computation

- i) Allotment under this system shall be made to Manufacturer-Exporters' who have undertaken substantial modernisation and upgradation of technology in their plant and machinery during the base period. Such plant and machinery shall meet the eligibility criterion of the Technological Upgradation Fund Scheme currently in force.
- ii) Allotments under this system shall be only for the export of goods manufactured in the modernised and upgraded production unit.
- iii) The allottees shall, at the time of certification of shipments, submit an affidavit that the goods being exported have been manufactured in their production units so modernised/upgraded.
- iv) For the year 2000, the base period will be four years i.e., from 1.7.95 to 30.6.99. However, from the allotment year 2001, the base period will be three years. For example, the base period for year 2001 will be 1.7.1997 to 30.6.2000, base period for year 2002 will be 1.7.1998 to 30.6.2001 and so on. In case of year 2000, the applications will be invited as per guidelines to be issued separately.
- v) Applications for MEE will be received by ED, TEXPROCIL upto 30th September of the previous year. An application under this system shall be accompanied by a demand draft for Rs. 500/- drawn in favour of ED, TEXPROCIL. The other terms and conditions of the application will be determined by the Textile Commissioner in consultation with ED, TEXPROCIL and after getting approval from the Ministry of Textiles.
- vi) Available quantities under the MEE will be distributed by the 'Quota Administering Authority' concerned on the basis of the production capacity of eligible applicants. Each eligible applicant may opt for a maximum of five categories for the above allotment.

Allotment, Utilisation and Transferability

- vii) MEE should be allotted in two parts, each consisting of 50% of the allotment. The first part will be valid from the date of allotment till the 31st May and second part will be valid till 30th September.

- viii) In case of MEE valid till 31st May, the quota holder shall get the endorsement on the certification of shipment in respect of the entitlement by 31st May. The certification will be valid for shipment upto 20th June of the quota year. Unutilised quotas (non-certified or non-shipped) shall lapse
- ix) In case of MEE valid till 30th September, the quota holders can get the extension till 31st December on payment of BG/EMD at the rates and subject to other conditions mentioned in 5(vi), mutatis-mutandis.
- x) The applications for such extension shall be submitted, complete in all respects, before the expiry of the initial validity of the entitlement or within a grace period of three working days
- (xi) MEE shall NOT be transferable

7. POWERLOOM EXPORTERS' ENTITLEMENT (PEE) SYSTEM.

The Textile Commissioner will separately notify detailed guidelines and norms of eligibility for allotments under the PEE System after obtaining approval from the Ministry of Textiles

8. READY GOODS ENTITLEMENT (RGE) SYSTEM

Release Schedule

- i) Entitlement under the RGE System will be opened four times in the year 40% of such entitlement will be released on the 10th of January, 30% on the 10th of April, 20% on the 10th of July and 10% on the 10th of October.
- ii) In addition to the quantities under this system, those that become available by way of surrenders, flexibilities or otherwise, may be released at any time, after giving adequate notice to the trade by the Quota Administering Authority concerned with the approval of the Ministry of Textiles.

Applications

- iii) Quantities shall be allotted against applications and on a day when available quantities are oversubscribed, eligibility shall be decided on the basis of unit value realisation among the applications received on that day.

Validity of allotments

- iv) Allotments will be valid for 50 days from the date of allotment. No extension will be granted.

System of allotment

- v) Allotments under the RGE system would be subject to EMD/BG @ 5% of FOB value of the quantity involved.
- vi) The Textile Commissioner may fix the maximum quantity, that can be applied for by an applicant for each country-category under this system per day in consultation with the Quota Administering Authority concerned.

Transferability

- vii) RGE allotments will NOT be transferable.

Reservation for Handlooms

- viii) Under US category 363 a quantity of 1 lac pieces of terry towels would be reserved for handlooms. The Ministry may also reserve quantities for handlooms under any other applicable country/category.

9. VALIDITY OF CERTIFICATION

- i) Validity of certification under the RGE System will be for a period of 50 days from the date of allotment unless otherwise specified.
- ii) Validity of PPE/MEE/PPT will be 50 days from the date of endorsement of the shipping bill or till the expiry of the entitlement certificate, whichever is earlier.
- iii) Notwithstanding the averments in para 8(iv) above, the Textile Commissioner may grant extension of validity period upto three working days in individual cases if he is satisfied that the exporter concerned could not export within the period due to circumstances beyond his control.

10. SLOW-MOVING ITEMS

- i) An item shall be notified as slow-moving, if, during the base year the utilisation has been less than 75% of the annual level for that year. The Quota Administering Authority shall notify the items that are slow moving, latest by 1st December of the previous year.
- ii) Notwithstanding anything else contained in any of the provisions of this notification, for slow-moving items, EMD/BG would be charged @ 1% of FOB value for shipment under the Ready Goods Entitlement System.
- iii) The quantitative ceiling stipulated for the RGE system vide 8(vi) above shall not be enforced.
- iv) This relaxation may, however, be withdrawn without advance notice.

11. PROVISIONS REGARDING SUBMISSION AND FORFEITURE OF EARNEST MONEY DEPOSIT/BANK GUARANTEE/POST DATED CHEQUE

- (i) EMD shall ordinarily be furnished by way of Demand Draft, FDR unilaterally encashable by the Quota Administering Authority or Bank Guarantee. However, Post Dated Cheques will also be accepted as EMD in systems other than RGE, subject to the conditions stipulated below:
 - (a) Post Dated Cheques will be accepted as EMD, in systems other than RGE, for extension of entitlements subject to the condition that if the cheque is dishonoured on deposit for any reason, the quantities extended against such cheques would be debited to any future entitlements of the concerned exporter concerned and he will not be allotted any further entitlements until the amount covered by the forfeiture is remitted by way of Demand Draft. This will be besides any other legal or other remedy which the Quota Administering Authority may decide to take.
 - (b) The Post Dated Cheques should be dated 1st June of the year following the year of allotment and should be valid for presentation during a period of 6 months from that date.
 - (c) The stipulations relating to release/forfeiture of the Post Dated Cheques would be the same as applicable to the other forms of EMD/BG.
- ii) The EMD/BG/Post Dated Cheque of an exporter who exports 90% or more of the entitlement would be released in full. However, in the case of slow moving items, this percentage will be 75% or more.
- iii) The 'Quota Administering Authority' shall forfeit the EMD/BG in case utilisation is 75% or more but less than 90% in case of fast moving items and 50% or more but less than 75% in case of slow-moving items proportionate to the shortfall in utilisation.
- iv) If utilisation is less than the above, i.e. less than 75% in case of fast moving items and 50% in case of slow moving items, the EMD/BG/Post Dated Cheque shall be forfeited in full.
- v) For the above purpose, utilisation shall be compiled on the basis of individual entitlements or on the basis of each System separately or on the request of the exporter for his performance in all systems (except RGE System) clubbed together.
- vi) A show cause notice shall be issued before forfeiture.
- vii) The quota administering authority should despatch the order of forfeiture of BG/EMD/PDC etc., by registered post with acknowledgement due card or preferably through speed post. Evidence of despatch of an order through the means specified above as also of acknowledgement/receipt thereof or otherwise should be kept on the file concerned.

- viii) All forfeited EMD/BG/Post Dated Cheques shall be deposited into a Public Deposit Account of the Government in such manner as Government directs from time to time.
- ix) The Quota Administering Authority, for ensuring the recovery of the amount of forfeiture may temporarily debar the exporter from obtaining entitlements and participating in the Export Entitlement Distribution Scheme for a specified period.

12. GUIDELINES FOR OBTAINING RELEASE OF HELD-UP CONSIGNMENTS

- (a) When a shipment effected in an unrestrained category is reclassified by the importing country into a restrained category or when a shipment effected in a restrained category is reclassified by the importing country into another restrained category, Export Certificates / Visas will be issued in the reclassified category after the exporter surrenders the quantity involved in the reclassified category. For this purpose, the exporter can surrender the quantity from own entitlements in systems other than RGE or by obtaining the quantity by transfer. If the case is to be cleared after 20th September, when transfers are not permissible, and an exporter does not have own entitlements to surrender, an undertaking to surrender the requisite quantity by the 31st January from the succeeding year's entitlement (own or transferred) shall be taken from such an exporter. Such an undertaking should be backed by BG/EMD to the extent of 50% of the value of the quantity calculated at the rates mentioned in para 5(vi). Once the quantity is surrendered, the BG/EMD may be released. If the quantity is not surrendered as per the undertaking, the BG/EMD may be forfeited. In such cases, PPE allotments in any country-category to the exporter for the succeeding year may be allotted, only after the requisite quantity is so surrendered.
- (b) If unallocated balance is available in the reclassified categories from the quantities released by the Quota Administering Authority in RGE system, the Export Certificate / visas for the held up consignment will be issued after debiting such balance and the exporter will not be required to surrender any quantity.
- (c) The stipulations of (a) and (b) above will also apply to cases where a change of buyer is required for a shipment that had been effected under the RGE system or under the PPE/MEE system after obtaining extension beyond 30th September and to cases where a change of importing country is required.
- (d) Where a shipment exported in a restrained category reclassified into another restrained category as above, the entitlement used for sending the shipment from the country may be returned to the exporter, subject to the following conditions .
 - (i) The exporter returns the Original Export Certificate / Visa to the Quota Administering Authority concerned.

- (ii) The Entitlement Certificate which had been debited at the time of export, remains valid for the concerned quantity when the add-back is requested.
- (e) In the case of items exported as handloom garments exempted from restraints or as "India Items", which are reclassified by the importing countries as restrained items, Visas / Export Certificates will be issued by the Quota Administering Authority after obtaining the approval of the Ministry of Textiles.

13. CLEARANCE BY CUSTOMS

- i) **Products under restraint** : Shipments will be allowed by Customs authorities at the ports of shipment after verifying the certification of export entitlement on the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the Quota Administering Authority concerned or any other appropriate agency designated for this purpose
- ii) **Handloom Products** : Insofar as export of all handloom fabric/made-up items corresponding to restrained items are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of Inspection endorsement by the Textiles Committee in para-2 of the combination form.
- iii) **Made-up items falling under "India Item"** : In respect of "India Items" which are traditional folklore handicraft textile products of India, shipments will be permitted by the Customs for export to the USA, the EU, Canada on the basis of appropriate certificates issued by the office of the Development Commissioner (Handicrafts).

14. EXPORT CERTIFICATE, CERTIFICATE OF ORIGIN & VISA

The following certification required under the relevant Bilateral Arrangements will be issued by the Quota Administering Authority concerned or any other body duly authorised in this behalf:-

- i) **USA:** Visa for all yarn, fabric (except Handloom) and made-ups (including Handloom) consignments of commercial value will be issued by TEXPROCIL.
- ii) **E.U :** (a) Export Certificate and Certificate of Origin for all restrained items of yarn, fabrics and made-ups except Catg.3/3(a) and Catg 23 will be issued by ED, TEXPROCIL (b) Export Certificate and Certificate of Origin for EU categories 3/3(a) & 23 will be issued by ED, SRTEPC. (c) Certificate of Origin for all non-restrained items will be issued by the Quota Administering Authority concerned.
- iii) **Canada:** Export Certificates for Fabric {except Catg. 31(a)} and Made-up items, which are subject to restraint, except for consignments valued at less than Canadian dollars 500/- will be issued by ED, TEXPROCIL. Export Certificate for Catg. 31(a) will be issued by ED, WVEPC.

15. HANDLOOM EXEMPT CERTIFICATE

In the case of export of all handloom fabric/made-up items corresponding to restrained items for Canada, all handloom fabrics and made-up items for the EU and the USA the Textile Committee will issue the Certificate as prescribed in the respective Bilateral Arrangements for such products.

16. APPEAL AGAINST FORFEITURE OF EMD/BG/POST DATED CHEQUE

- i) Any exporter aggrieved by the order of forfeiture of EMD/BG by the quota administering authority may file an appeal to the 1st appellate authority, i.e., the Textile Commissioner within 45 days of the despatch of the order of the quota administering authority. This appeal shall be made in triplicate, accompanied by a demand draft for Rs. 500/-, drawn in favour of the Textile Commissioner and payable at Mumbai.
- ii) The appellant may make a separate application for stay of the order of the quota administering authority if he so desires.
- iii) The Textile Commissioner will decide the issue of stay, as early as possible.
- iv) A Decision on the appeal will also be taken as early as possible, preferably within two months. A reasonable opportunity for personal hearing, if requested by the appellant, shall be given to him. The final order will be despatched through registered post (with acknowledge due card) or preferably through speed post and the evidence of despatch thereof by the said means, as also of acknowledgement/receipt thereof or otherwise shall be placed on the file concerned.
- v) In the case of appeals which have been filed after the due date, the Textile Commissioner shall first decide as to whether such delay is to be condoned or not. The Textile Commissioner shall pass speaking order in such cases.
- vi) For the above purposes, the Textile Commissioner shall mean and include such other officer (not below the rank of Director) to whom the Textile Commissioner expressly or otherwise delegates the necessary responsibilities.
- vii) If an exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner in the matter of a stay application or an appeal, he may prefer an appeal against such decision within 45 days of the despatch of the order of the 1st appellate authority to the 2nd appellate authority for a decision thereon.
- viii) The 2nd appellate committee for these purposes will comprise the following:

(a) Joint Secretary (Exports), MOT, GOI	Chairman
(b) An officer of the Ministry of Law & Justice, GOI (not below the rank of Dy. Secy. to the GOI)	Member
(c) An officer of the DGFT, MOC, GOI (Not below the rank of Dy. Secy to the GOI)	Member
(d) Dy. Secretary/Director (Exports), MOT, GOI	Member-Secretary

The quorum of the this committee will consist of its Chairman and 2 members.
- ix) Any appeal before the 2nd appellate authority shall be addressed to its Member-Secretary in a set of five copies, accompanied by a demand draft for Rs. 500/-, drawn in favour of the Ministry of Textiles, GOI and payable at Delhi

- x) If matter of the appeal also pertains to a stay and is of an urgent nature, the Chairman of the committee may grant the stay by recording reason(s) in writing.
- xi) The 2nd appellate authority shall also decide the case at the earliest, preferably within three months.

17. PROCEDURE TO DEAL WITH QUOTA MALPRACTICES BY EXPORTERS

- i) The Committees called the Enforcement Committees are constituted with the following composition:-

1) Textile Commissioner, MOT, GOI	Chairman
2) Quota Administering Authority	Member
3) An officer of the Ministry of Law & Justice, GOI (not below the rank of Dy. Secy. to the GOI)	Member
4) Chairman of the agency concerned (TEXPROCIL, SRTEPC and WVEPC, as the case may be)	Member
5) An Officer of the Agency concerned (To be nominated by Quota Administering Authority in consultation with the Chairman of the Enforcement Committee)	Member-Secretary
- (ii) The Chairman and two members will constitute the quorum.
- (iii) The Enforcement Committees will deal with cases involving the use of any one of the following, in connection with obtaining, extending, utilising or proving the utilisation of quotas :-
 - a) Any fraudulent activity
 - b) Any misrepresentation of facts
 - c) Any falsification of documents or forgery
 - d) Submission of post-dated cheques for extension of entitlements which are dishonoured on presentation to his bank.
- (iv) The Enforcement Committees will also deal with cases relating to exporters who are found to have exported or who have completed the formalities to export any item, which contains any dyes, chemicals, pigments or other material whose handling is specifically banned by the competent authority of the Government.
- (v) In cases where the Committee finds the exporters guilty of fraud or other irregularities, which are violative of any of the above provisions, after examining his explanation and giving a personal hearing, the exporter may be debarred from obtaining entitlements and participating in the Export Entitlement Distribution Scheme for a specified period.
- (vi) In serious cases, the exporter may be temporarily debarred by the Quota Administering Authority before personal hearing, pending the completion of the procedures and finalisation of a decision by the Committee.

- (vii) The Enforcement Appellate Committee with the following composition will hear appeals against the decisions of the Enforcement Committees:
- | | | |
|------|--|-------------------|
| i) | Joint Secretary (Exports), MOT, GOI | Chairman |
| ii) | An officer of the Ministry of Law & Justice, GOI
(Not below the rank of Dy. Secretary to the GOI) | Member |
| iii) | An officer of the O/o the DGFT, MOC, GOI
(Not below the rank of Dy. Secretary to the GOI) | Member |
| iv) | Dy. Secretary/Director (Exports), MOT, GOI | Member-Secretary. |
- (viii) The quorum of the Enforcement Appellate Committee will consist of the Chairman and 2 members. The Chairman of the Enforcement Appellate Committee will, however, have the power to grant stay on the orders passed by the Enforcement Committee, after giving reasons recorded in writing.
- (ix) Any appeal filed before the Enforcement Appellate Committee will be presented in five sets of papers accompanied by a demand draft for Rs.500/-, drawn in the favour of the Ministry of Textiles, GOI.
- (x) The Enforcement Appellate Committee may review and amend, modify or quash the orders of the Enforcement Committees on appeal from an aggrieved exporter or by initiating the action suo-moto.

18. SUPERVISORY ROLE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

The Textile Commissioner shall exercise general supervision over the matters relating to implementation of this Policy. In case, any deviation is noticed by the Textile Commissioner, it shall be promptly reported to the Ministry of Textiles seeking directions thereon.

19. COORDINATION COMMITTEE

A Coordination Committee consisting of Textile Commissioner, the representatives of EPCs (AEPC, TEXPROCIL, SRTEPC and WVEPC) including the Quota Administering Authorities, ED, HEPC, DC(HC) and Dy. Secretary/Director (Exports) will meet under the chairmanship of the Joint Secretary (Exports) once in three months to review the operation of the policy. The Committee will send a report to the Ministry for taking appropriate actions on any changes desired in the Policy.

20. RIGHT OF THE GOVERNMENT TO MAKE AMMENDMENT

Government reserves the right to make amendments to and of the foregoing provisions in the public interest, without giving prior notice.

N. RAMAKRISHNAN, Jt. Secy.